ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-9* October (Part-1) 2021
Innovation The Research Concept

रायपुर, (छत्तीसगढ़) में स्लम आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति : एक अध्ययन

Socio-Economic Status of Slum Population in Raipur, (Chhattisgarh): A Study

Paper Submission: 10/10/2021, Date of Acceptance: 21/10/2021, Date of Publication:23/10/2021

प्रदीप कुमार एक्का
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
राजीव गांधी शासकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अम्बिकापुर सरगुजा
(छ.ग.) भारत

सारांश

भारत में शहरी जनसंख्या वृद्धि का त्वरण 10-15 वर्षों से अनुभव किया गया है क्योंकि भारत के मानचित्र में नए राज्यों और नए जिलों का गठन किया गया है। हाल के वर्षों में झुग्गी-झोपड़ियों की आबादी कई गुना बढ़ गई हैरू इसके कारण है-

1. बड़े कस्बों और शहरों में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता।
2. ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में आजीविका के साधनों की उपलब्धता।

इसका तात्पर्य यह है कि ग्रामीण गरीबी शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाती है। भौतिक बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता के बावजूद ग्रामीण लोग विशेष रूप से आर्थिक कारणों से शहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। वे आवास सुविधा खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्हें पेयजल आपूर्ति की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

प्रवासियों की निरंतर आमद के कारण जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक सेवाओं और अन्य बुनियादी ढांचे की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। प्रवासन आवास की समस्याएं पैदा करता है; नतीजतन, झुग्गी-झोपड़ियों और अनाधिकृत बस्तियों के तेजी से बढ़ने के संदर्भ में अनौपचारिक समाधान खोजने होंगे।

The acceleration of urban population growth in India has been experienced over 10-15 years as new states and new districts are formed in the map of India. The population of slums has increased manifold in the recent years due to-

1. Availability of employment opportunities in large towns and cities.
2. Availability of means of livelihood in urban areas as compared to rural areas.

This implies that rural poverty shifts to urban areas. Despite the non-availability of physical infrastructure, rural people are attracted to urban areas especially for economic reasons. They struggle to find accommodation. They are facing shortage of drinking water supply.

The continuous influx of migrants has affected the quality of life, resulting in a widening gap between demand and supply of essential services and other infrastructure. Migration creates housing problems; Consequently, informal solutions have to be found in the context of the rapid growth of slums and unauthorized settlements.

मुख्य शब्दः रायपुर, (छत्तीसगढ़) में स्लम आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
Keywords: Socio-Economic Status of the Slum Population in Raipur, (Chhattisgarh).

प्रस्तावना

सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और विशेष क्षेत्र/समाज/समुदाय की सामाजिक धारणा के अनुसार, स्लम की अवधारणा और अर्थ अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है। शहरों के अलग-अलग राज्यों में मलिन बस्तियों के अलग-अलग नाम हैं। दिल्ली में, इसे ष्झुग्गी झोपड़ीष् के नाम से जाना जाता है, जबकि मुंबई में इसे ष्झोपड़ पट्टीष् या चॉल के नाम से जाना जाता है। यह कानपुर में अहतस, कोलकाता में बस्ती, चेन्नई में ष्चेरिसष् बैंगलोर में ष्केरिसष् और रायपुर में ष्गंदी बस्तीष् है। हालांकि, अधिकांश मलिन बस्तियों में भौतिक विशेषताएं अनिवार्य रूप से समान हैं। वे आम तौर पर जीर्ण-शीर्ण और दुर्बल संरचनाओं वाली झोपड़ियों का एक समूह होते हैं, जिनमें सामान्य शौचालय की सुविधा होती है, बुनियादी सुविधाओं की कमी, जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था और ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त व्यवस्था होती है। इस प्रकार वहाँ रहने वालों की स्थिति अत्यधिक कष्टप्रद हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप निवासियों के लिए वायु और जल जनित रोग होते हैं।

स्लम एरिया इम्प्रूवमेंट एंड क्लीयरेंस एक्ट 1956 की धारा 3 के तहत, मलिन बस्तियों को ष्उन आवासीय क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां आवास किसी भी तरह से जीर्ण-शीर्ण, भीड़भाड़, दोषपूर्ण व्यवस्था और ऐसे भवनों के डिजाइन, संकीर्णता के कारण मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हैं। सड़कों की दोषपूर्ण व्यवस्था, वेंटिलेशन की कमी, प्रकाश या स्वच्छता सुविधाओं या इन कारकों के किसी भी संयोजन जो सुरक्षा, स्वास्थ्य और नैतिकता के लिए हानिकारक हैं।

Scanned by CamScanner

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-9* October (Part-1) 2021
Innovation The Research Concept

इसलिए, मलिन बस्तियाँ सघन भीड़-भाड़ वाले आवासीय क्षेत्र हैं जो एक या अधिक बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण रहने के लिए अनुपयुक्त हैं।

झुग्गी-झोपड़ी आबादी का क्षेत्रवार जनसांख्यिकी वितरण क्षेत्र-वार

पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा शामिल हैं। पश्चिम क्षेत्र में महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं। दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।
मध्य क्षेत्र में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तरप्रदेश और राजस्थान शामिल हैं।
उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, हरियाणा, उत्तरांचल, चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू और कश्मीर शामिल हैं।

1. यह स्पष्ट है कि झुग्गी आबादी का वितरण पश्चिमी क्षेत्र (30.69ः) और मध्य क्षेत्र (22.9ः) और उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र (22.6ः) में केंद्रित है।
2. यह भी अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों में झुग्गीवासियों को अपने आवास, भोजन और कपड़े, सुरक्षित पेयजल की सुविधा, आजीविका, रोजगार आदि के संबंध में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
3. विशेष रूप से पूरा वातावरण इतना दयनीय हो जाता है कि कोई इसमें रहने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि, इन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को ऐसा जीवन जीने की आदत हो गई है।
4. उनके लिए कोई स्पष्ट भविष्य नहीं है। वे जिस संस्कृति और परिस्थितियों में रह रहे हैं, उससे संतुष्ट प्रतीत होते हैं।
5. जब कोई छत्तीसगढ़ के स्लम-निवासियों के आंकड़ों की तुलना भारत के आंकड़ों से करता है, तो वह दिखाए गए आंकड़ों (1.9ः) से बहुत खुश और संतुष्ट हो जाता है।
6. छत्तीसगढ़ में कुल शहरी आबादी में से 19.54ः की कुल आबादी मलिन बस्तियों की कठिन स्थिति में रह रही है, जिसे महाराष्ट्र (27.3ः), आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में ष्औसत स्लम आबादीष् कहा जा सकता है। 24.9ः) और हरियाणा (23.2ः)।
7. नहीं के संदर्भ में। मलिन बस्तियों में, यह ध्यान दिया जाता है कि दक्षिणी क्षेत्र (30.0ः) और मध्य क्षेत्र (29.0ः) में क्रमशः अधिकतम हिस्सा है। राज्य-वार, यह पाया गया है कि ए.पी. (77) ने पहला स्थान प्राप्त किया, उसके बाद यू.पी. (69), तमिलनाडु (63), महाराष्ट्र (61) और पश्चिम बंगाल (59)।
8. बड़े और महानगरीय शहरों वाले ये सितारे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासियों और अन्य राज्यों के लोगों को आकर्षित करते हैं; इसलिए नहीं। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या बढ़ी है और बढ़ती दर से बढ़ रही है।
9. संक्षेप में, झुग्गी-झोपड़ी के निवासी दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में केंद्रित हैं। छत्तीसगढ़ मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और अधिकांश झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले राजधानी शहर रायपुर में पाए जाते हैं

भारत में झुग्गियां

2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी के मुकाबले कुल झुग्गी आबादी 14.88ः है। कुल झुग्गी आवादी में से, 14.3ः 0-6 आयु वर्ग के हैं, 17.4ः जनसंख्या अनुसूचित जाति से संबंधित है और 2.4ः अनुसूचित जनजाति आबादी से संबंधित है।
कुल ६२.७ः आबादी है, जिन्होंने शैक्षिक केंद्रों का दौरा किया है, हालांकि वे स्लम में रहने और भीड़भाड़, परिष्कृत और भीड़भाड़ वाले जीवन के लिए मजबूर हैं। मुख्य कामगारों की स्लम आबादी में भारत में मुख्य कामगारों की शहरी आबादी (83818431) के मुकाबले 15.07ः है। मुख्य श्रमिकों में, भारत में केवल 0.9ः लोग खेती पर निर्भर हैं, 2.2ः खेतिहर मजदूरों से संबंधित हैं, 4.6ः घरेलू उद्योगों में शामिल हैं। लोगों का बहुत बड़ा प्रतिशत (92.3ः) है, जिन्होंने स्वयं को व्यवसायिक गतिविधियों में संलग्न किया है। तथ्य यह है कि स्लम क्षेत्र में लोगों के पास भूमि का अधिक भाग नहीं है; इसलिए यह स्पष्ट है कि उन्हें निर्माण कार्यों के बजाय खेती के काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुल शहरी सीमांत श्रमिकों में से 39.90ः आबादी स्लम क्षेत्र में रहती है। कुल 13,80,964 सीमांत कामकाजी आबादी में से केवल एक प्रतिशत (1ः) खेती में शामिल है, जबकि 8.7ः लोग खेतिहर मजदूर के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुल 9.5ः सीमांत कामगारों ने खुद को घरेलू औद्योगिक क्षेत्रों में लगाया है। अन्य श्रमिकों या स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक कर्मियों में उनमें से अधिकांश 80.9ः के बराबर हैं। ज्ञायतव्य है कि - लोग औपचारिक गतिविधियों की तुलना में गैर-औपचारिक गतिविधियों में अधिक रुचि लेते हैं। लोग स्व-व्यवसाय से संतुष्ट हैं, जहां उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। वहाँ हमें किसी भी कंपनी या संस्था के बॉस से इस तरह के काम में आज़ादी मिलती है। वे अपने स्वयं के व्यवसाय के मालिक हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों श्रेणियों (मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक) में, अधिकांश लोग अन्य श्रमिकोंष् में शामिल रहे हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य निश्चित रूप से इस छत्तीसगढ़ ढ़ की राजधानी रायपुर में झुग्गी-झोपड़ी के लोगों की स्थिति को समझने के लिए करना है, और विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया देना है। जरूरतें, अवसर और चुनौतियाँ जो इसने हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। उस पर चिंतन करना है।

Scanned by CamScanner

ISSN: 2456–5474
RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-9* October (Part-1) 2021
Innovation The Research Concept

छत्तीसगढ़ में झुग्गियां

छत्तीसगढ़ की स्थिति के संबंध में कुल सं. शहरी आबादी का 4195747 (सर्वेक्षण, 2001) है जिसमें भारतीय शहरी आबादी के मुकाबले 14.66ः शामिल है। छत्तीसगढ़ की दी गई कुल शहरी आबादी में से, स्लम आबादी 817908 है, जिसमें कुल मिलाकर 19.54ः है। हालांकि, जब भारतीय स्लम आबादी की तुलना में यह सिर्फ 1.92ः है। हालांकि यह आंकड़ा बहुत छोटा दिखता है लेकिन झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों और शहरी आबादी की संख्या में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ मे शहरी आबादी का 0-6 आयु वर्ग की शहरी जनसंख्या कुल संख्या की तुलना में 14.2ः है। छत्तीसगढ़ के स्लम क्षेत्र में 0-6 आयु वर्ग के लोगों की संख्या छत्तीसगढ़ में स्लम-निवासियों की कुल संख्या की तुलना में 15.4 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ शहरी में अनुसूचित जाति की आबादी के संबंध में 143533 (17.5ः) लोग स्लम क्षेत्रों में रह रहे हैं, जबकि कुल संख्या 143533 है। 519667 (12.4ः) शहरी अनुसूचित जाति की आबादी। शहरी छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.4ः है जिसमें 351761 आबादी है। इस श्रेणी में स्लम-निवासी कुल स्लम-निवासियों के 64945 (7.9ः) के बराबर हैं।

छत्तीसगढ़ में शहरी आबादी की साक्षरता दर के संबंध में कुल शहरी आबादी के मुकाबले 2886538 (70.0ः) है, जबकि छत्तीसगढ़ में स्लम आबादी की साक्षरता दर शहरी आबादी के मुकाबले 517363 (17.92ः) और कुल स्लम के मुकाबले 63.3 है। यह अनुमान लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में मुट्ठी भर लोग (17.92ः) साक्षर हैं। उल्लेखनीय है कि कुल 92.1ः स्लमवासी छोटे या बड़े पैमाने पर अपना स्व-व्यवसाय कर रहे हैं।

बाल श्रम

Sno	State	Total Child Labors (lacs)
1	Chhattisgarh	3.64
2	Orissa	4 07
3	Jharkand	19
4	Uttar Pradesh	10 6
5	Madhya Pradesh	8 57
6	West Bengal	13 6
7	Rajastan	12.6
8	Bihar	11
9	Tamil Nadu	4 18

रायपुर शहर में झुग्गियां

जिले की कुल जनसंख्या (3289782) में से 605747 (18.417ः) जनसंख्या शहरी रायपुर में निवास करती है। इसके अलावा, कुल शहरी आबादी (605747) में से, कुल संख्या। 226151 यानी 37.33ः लोग अस्वच्छ और भीड़भाड़ वाली झुग्गी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

इसी प्रकार, 0-6 आयु वर्ग के बीच की जनसंख्या, रायपुर जिले की जनसंख्या के मुकाबले शहरी आबादी का 2.55ः (83943) है, और रायपुर में झुग्गी आबादी (आयु समूह 0-6) 42.61ः है (कुल शहरी रायपुर आबादी (83943) के मुकाबले 35770)।

0-6 आयु वर्ग के लगभग आधे बच्चे गंदे वातावरण में रहने को मजबूर हैं, जहाँ हवादार वातावरण नहीं है। लगता है उनका बचपन फीका होता जा रहा है। कोई और उनका उज्जवल भविष्य नहीं है। शहरी रायपुर में कुल शहरी अनुसूचित जाति की आबादी के मुकाबले स्लम क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों की कुल संख्या 43932 है, जो (58.35ः) हैं। रायपुर में शहरी अनुसूचित जाति की आबादी को ध्यान में रखते हुए यह काफी बड़ा आंकड़ा है। इसी प्रकार नगरीय रायपुर में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (23580) में कुल संख्या। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या 9937 है, जो 42.14ः है। हालांकि, रायपुर जिले की कुल जनसंख्या (3289782) के साथ तुलना करने पर, मलिन बस्तियों में रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी क्रमशः1.33ःः और 0.302ः है।फिर से जब रायपुर शहर में कुल स्लम आबादी (368956) के साथ तुलना की जाती है, तो झुग्गी में रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी क्रमशः 11.9ः और 2.69ः है। साक्षरता दर के संबंध में, 426909 लोग हैं, जिनमें कुल शहरी आबादी के मुकाबले 7.4ः शामिल हैं, जिन्हें साक्षर माना जाता है, जबकि कुल झुग्गी-झोपड़ियों में से 62.5ः लोग साक्षर पाए जाते हैं। हालांकि, रायपुर जिले की कुल जनसंख्या (3289782) की तुलना में शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर 12.97ः और स्लम क्षेत्र 4.29ः है।

इन मलिन बस्तियों का क्षेत्रवार वितरण इस प्रकार है

Scanned by CamScanner

रायपुर में स्लम जनसंख्या वितरण (जोन–वार)

SN	ZONE	% OF SLUMS
1.	South zone	30%
2.	West zone	16%
3.	Central zone	29%
4.	North zone	12%
5.	East zone	13%

यह स्पष्ट है कि 68 मलिन बस्तियाँ हैं, जिनमें परिवार में 5-10 औसत सदस्य हैं, इसके बाद 55 मलिन बस्तियाँ हैं, जहाँ हम औसत परिवार के सदस्यों को 10-15 के बराबर पाते हैं, इसी तरह 15-20 औसत परिवार के आकार के साथ 31 मलिन बस्तियाँ हैं। यह आश्चर्यजनक है कि 27 फिसदी ऐसे हैं जिनमें 20 से अधिक और 50 से कम औसत परिवार के सदस्य हैं, यानी 20झ50 परिवार का आकार। फिर से 8 ऐसी मलिन बस्तियां हैं, जिनमें 50 से अधिक परिवार आकार हैं। इतना ही नहीं, सुंदरलाल शर्मा वार्ड में सुंदर नगर क्षेत्र नाम की झुग्गी 142-परिवार के आकार की है। यह अवास्तविक प्रभाव और अविश्वसनीय है। इसी प्रकार, पयारेलाल वार्ड की स्वीपर कॉलोनी में औसत परिवार आकार के रूप में 82 और लक्ष्मी नारायण दास के अधीन दामीपारा स्लम में 67 औसत परिवार आकार हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू वार्ड में जोरापीरा में 56 औसत परिवार आकार हैं। औसत पारिवारिक आकार के जो आंकड़े दिखाए गए हैं, व्यावहारिक मानव जीवन में अवास्तविक, अप्रासंगिक हैं। ये आंकड़े अप्रासंगिक और संदिग्ध प्रतीत होते हैं। सबसे कम औसत परिवार आकार (04) स्वामी आत्मानंद वार्ड के अर्जुन नगर और कन्हैयालाल बंजारी वार्ड के गुड़ियारी में पहचाना गया है। इन मलिन बस्तियों का एक आदर्श परिवार आकार है। मूल्यांकन दल ० से 10 औसत परिवार के आकार को एकल परिवार मानता है, जिनकी संख्या 70 है। फिर से 10 से 20 के औसत परिवार को संयुक्त परिवार माना जाता है, जबकि 20 से 55$ को विस्तारित परिवार के रूप में लिया जाता है। एकाकी परिवार के सदस्य आय अर्जन के मामले में अपने रहन-सहन के तरीके से संतुष्ट प्रतीत होते हैं। उनके पास भविष्य के लिए बचाने के लिए भी कुछ है। उनके पास मोटरसाइकिल, साइकिल, टीवी, रेडियो, घड़ियां आदि जैसी कुछ संपत्तियां हैं, हालांकि वे खतरनाक परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं। उनके पास सुरक्षित पेयजल की सुविधा का अभाव है।

ऐसे परिवारों में, बच्चों (लगभग 90ः) ने अपना नामांकन कराया है। माता-पिता भी शिक्षा के महत्व से अवगत हैं। उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया है। समाज का यह वर्ग (झुग्गी-झोपड़ी) स्वास्थ्य सुविधाओं और दवाओं के प्रति काफी जागरूक है। इसलिए, वे इन सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम हैं। विशेष रूप से बच्चों के लिए पल्स-पोलियो और अन्य टीकाकरण जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रम नियमित रूप से कराये जाते हैं। इन लोगों की मानसिकता निश्चित रूप से जीवन की गुणवत्ता और इसके निरंतर विकास के प्रति सकारात्मक है। हालांकि, कुछ ऐसे भी हैं, जो अभी भी खुद को बेरोजगार पाते हैं। इसलिए, वे नियमित कमाई के स्रोत रखना चाहते हैं। 10-20 परिवार आकार वाले संयुक्त परिवार भी आय-व्यय की दृष्टि से अपनी जीवन-शैली से संतुष्ट थे। हालांकि, इस मामले में, परिवार के अधिकांश सदस्य नहीं कमाते हैं, इसलिए शायद ही बचत होती है। कुछ लोगों के पास संपत्ति के रूप में मोटरबाइक, साइकिल, टीवी, रेडियो आदि हैं। इस तरह के आसपास का वातावरण बहुत चिपचिपा और बदबूदार है। लोगों को सफाई की कोई परवाह नहीं है। फलस्वरूप कोई ष्सुलभ शौचालय" नहीं है; सड़कें और नालियां हमेशा गंदी रहती हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब लोगों को पर्याप्त कपड़े और बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है। यहां भी यही स्थिति देखने को मिलती है, हालांकि लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, लेकिन आय के अभाव में वे अभ्यास नहीं करते हैं। कुछ पर्वो के समय और विशेष अवसरों पर लोग अधिक खर्च करते हैं। इसके लिए वे साहूकारों या कुछ व्यवसायियों के पास जाते हैं और उच्च ब्याज दर पर ऋण लेते हैं। वे ष्हाथ से मुंहष् प्रणाली पर निर्भर करते हैं। लोगों के इस वर्ग में शराब पीने की आदत है, जिसके बिना वे नहीं रह सकते। बहुत अधिक नशा करने के बाद, कई बार

Scanned by CamScanner

ISSN: 2456–5474
RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-9* October (Part-1) 2021
Innovation The Research Concept

वे अपनी पत्नियों और अन्य झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों से झगड़ते हैं। इस प्रकार वे मलिन बस्तियों में उपद्रव फैलाते हैं। हालांकि वे अन्य लोगों को बड़ी इमारतों में रहते और सफेदपोश नौकरी करते हुए देखते हैं, लेकिन उनके रहन-सहन और मानकों में बदलाव के कोई संकेत नहीं हैं। उनकी कोई उच्च महत्वाकांक्षा नहीं है। इसलिए वे भविष्य की परवाह नहीं करते कि वे क्या खाएंगे और क्या पीएंगे। वे सिर्फ वर्तमान में जीते हैं।

विस्तारित परिवारों का बड़ा परिवार आकार

नगर निगम रायपुर द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 35 मलिन बस्तियों की पहचान की गई है, जहां एक परिवार में 142 तक के 20 या अधिक सदस्य रहते हैं। कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि वे एक साथ कैसे रह रहे होंगे। इन झुग्गियों में भीड़भाड़ रहती है। रहने की स्थिति बिल्कुल प्रवाहकीय नहीं है। लोगों की मानसिकता आत्मचिंता की होती है। चूंकि एक परिवार में कई बच्चे/लोग हैं, माता-पिता और दादा-दादी उनकी चिंता नहीं करते हैं। कभी-कभी यह देखा जाता है कि माता-पिता को यह नहीं पता होता है कि एक परिवार में कितने बच्चे हैं। कमाई कम है, इसलिए जीवन दयनीय हो गया है। इनका स्वभाव चोरी का होता है। इन लोगों में और भी असामाजिक तत्व हैं।राजनीतिक रूप से, वे राजनीतिक स्थितियों से अवगत नहीं हैं। उन्हें राजनीतिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जहां भी चुनाव होता है, वे उन नेताओं का अनुसरण करते हैं जो अपने वोट के लिए सबसे अधिक भुगतान करते हैं। राजनीतिक मामलों में लोगों का दिमाग स्थिर नहीं होता है। कमाई कम होने के कारण लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाओं आदि के मामले में पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। उनके पास ज्यादा बचत नहीं है। वे हाथ से मुंह स्थिति में भी रह रहे हैं। इन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग समस्याओं से घिरा जीवन व्यतीत करते हैं। वे सामाजिक गतिविधियों में रुचि नहीं लेते हैं। पीने के पानी, बिजली आदि के संबंध में एक आम समस्या होने पर वे एक साथ आते हैं। कुछ त्योहारों और विशेष अवसरों पर लोग साहूकारों, बड़े व्यापारियों के पास कर्ज के लिए जाते हैं। अंततः वे वापस भुगतान करने के लिए असहाय हो जाते हैं। निम्नलिखित कहावत उनके जीवन पर सटीक बैठती है- ष्झुग्गीवासी कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में जीते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं ये लोग अपने जीवन और अपने आसपास के अन्य लोगों के प्रति उदासीन होते हैं। उनमें सामुदायिक जीवन का अभाव है। कुल मिलाकर, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मलिन बस्तियों में जीवन दयनीय, भीड़भाड़ वाला, अधिक भीड़-भाड़ वाला अस्वस्थ (शारीरिक, मानसिक, नैतिक रूप से) और अस्वच्छ है। लोग एचआईवी/एड्स के शिकार भी हो रहे हैं, जिसके विनाशकारी आर्थिक परिणाम होने के साथ-साथ नैतिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। तथाकथित मानवीय गरिमा और मानव-सम्मान का कोई मूल्य नहीं है। इन लोगों की स्थिति भीड़ में रहने वाले जानवरों जैसी है। अंतर केवल इतना है कि इन लोगों को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। रायपुर शहर में राज्य में बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है। द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद विभिन्न मलिन बस्तियों में यादृच्छिक रूप से कुछ प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह किया गया। यह समुदाय में केंद्रित समूह चर्चा के रूप में किया गया था। क्रॉस कटिंग मुद्दे इस प्रकार हैं: यह पाया गया कि समुदायों में किसी भी कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग का अभाव था। मलिन बस्तियों की कुल संख्या से, यह पाया गया कि महिलाएं घरेलू नौकरों के रूप में शामिल हैं; यहां तक कि मलिन बस्तियों में भी लड़कियां घरेलू नौकर के रूप में काम करती थीं। सभी मलिन बस्तियों में दिहाड़ी मजदूरों की उपस्थिति थी, जिनमें ज्यादातर पुरुष थे, यह भी कहा जा सकता है कि कुछ समुदायों में बाल मजदूर पाए गए क्योंकि लड़के और लड़कियां दिहाड़ी मजदूरों में शामिल हैं। अधिकांश झुग्गियों में रिक्शा चलाने वालों की उपस्थिति होती है, जो केवल पुरुष होते हैं, यहाँ तक कि कुछ झुग्गियों में भी इस पेशे में लड़के शामिल होते हैं। प्रच्छन्न मजदूरों के लिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है और जो दिन में सिर्फ दो बार भोजन के लिए काम कर रहे हैं, इस प्रकार के मजदूर सभी मलिन बस्तियों में बहुत अधिक हैं, उन्हें कम भुगतान किया जाता है और निष्कर्षों से यह पता लगाया जा सकता है कि अधिकांश मलिन बस्तियों में, कम उम्र के लड़के और लड़कियां मजदूरों के रूप में लगे हुए हैं। यह भी पाया गया कि अधिकांश प्रजनन/घरेलू कामगार महिलाओं और लड़कियों ने किया है, केवल प्रकाश और खाना पकाने के लिए ईंधन पुरुषों और लड़कों द्वारा एकत्र और प्रज्वलित किया जाता है। पुरुष सामुदायिक कार्य करते हैं। महिला लोक और ज्यादातर प्रजनन/घरेलू कार्य करती हैं। जब पुरुष और महिलाएं काम पर जाते हैं, तो लड़के और लड़कियां छोटे भाई-बहनों की देखभाल करते हैं, और घर का काम करते हैं। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण के कारण, महिलाओं की राजनीतिक शक्तियों पर पहुंच है, लेकिन नियंत्रण उनके पति और पुरुष सदस्यों के हाथों में है, वे उनके हाथों की कठपुतली हैं। स्थानीय निकायों में निर्वाचित सदस्यों के पतियों को निर्वाचित सदस्यों के रूप में सम्मानित किया जाता है; वे अपनी पत्नियों के लिए निर्णयकर्ता होता हैं।

Scanned by CamScanner

ISSN: 2456–5474

RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-9* October (Part-1) 2021

Innovation The Research Concept

SLno.	Problem category	Outcome
1.	Attitudes	Jealousy Ego, violent or aggressive personality
2.	Behaviours	Fighting, wife battering, petty to serious daily quarrels
3	Culture	High discrimination between castes and gender, denial of rights and liberties, insecurity

Protection:

Sl. No.	Category	Prevalence in slums
1	Presence of abusers	Yes
	○ Physical abuse	Yes
	○ Sexual abuse	Yes
	○ Emotional abuse	Yes
2.	Presence of protection committees	Nil
3.	Address to child related issues	Nil
4	Address to women related issues	State Mahila(women) commission

मलिन बस्तियों में मौजूद सुरक्षा तंत्र बहुत क्षीण है। सभी मलिन बस्तियों में, बच्चों और महिलाओं ने शिकायत की कि या तो कार्यस्थल या परिवार में, यहाँ तक कि पड़ोस में भी दुर्व्यवहार हो रहा है। किसी भी सुरक्षा समिति का अभाव है और समुदाय ने कभी भी बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित नहीं किया है, वे इसे व्यक्तिगत परिवारों की जिम्मेदारी मानते हैं न कि पूरे समुदाय की। राज्य की राजधानी में, महिला आयोग की मौजूदगी है, जो दर्ज की गई शिकायतों पर काम करता है, लेकिन खेद की बात यह है कि यह केवल पंजीकृत मामलों के साथ ही काम कर सकता है, लेकिन जैसा कि देखा गया है कि अधिकांश मुद्दे अपंजीकृत रहते हैं।

Raipur : Disabled Population

	Person	Male	Female
Total	71510	38561	32949
Rural	56052 (78.38%)	29883(77.49%)	26169 (79.42%)
Urban	**15458 (21.61%)**	**8678 (22.50%)**	**6780 (20.57%)**
In seeing (Total)	31372	15852	15520
Rural	25217 (80.38%)	12678 (79.97%)	12539 (80.79%)
Urban	**6155 (19.62%)**	**3174 (20.02%)**	**2981 (19.20%)**
In speech	4512	2521	1991
Rural	3387 (75.06%)	1865 (73.97%)	1522 (76.44%)

Scanned by CamScanner

ISSN: 2456–5474
RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-9* October (Part-1) 2021
Innovation The Research Concept

In hearing	5751	2949	2802
Rural	4947 (86.01%)	2547 (86.36%)	2400 (85.65%)
Urban	**804 (13.98%)**	**402 (13.63%)**	**402 (14.34%)**
In movement	22981	13428	9553
Rural	17666 (76.87%)	10155 (75.62%)	7511 (78.62%)
Urban	**5315 (23.12%)**	**3273 (24.37%)**	**2042 (21.37%)**
Mental	6894	3811	3083
Rural	4835 (70.13%)	2638 (69.22%)	2197 (71.26%)
Urban	**2059 (29.86%)**	**1173 (30.77%)**	**886 (28.73%)**

सभी विकलांगताएं जन्मजात प्रकृति की होती हैं, जिन्हें यदि टीकाकरण होता तो टाला जा सकता था। गतिविधियों के निम्नलिखित निवारक उपायों पर विचार करके इसे संबोधित किया जा सकता है-

1. गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना।
2. नवजात शिशु के बाद पहला स्तनपान सुनिश्चित करें।
3. टीकाकरण की प्राथमिक खुराक की अनदेखी या टीकाकरण से बचने के लिए कठोर मानसिकता

गर्भावस्था के समय उचित स्वास्थ्य देखभाल।

4. समय से पहले और कम उम्र में शादी से बचने के बारे में जागरूकता
5. लघु व्यवसाय और संबंधित गतिविधियों के माध्यम से आजीविका के लिए सहायता।

वातावरण

1. समुदाय को बेहतर स्वच्छता सुविधा
2. जल निकासी, सीवेज सिस्टम आदि का उचित निर्माण और प्रबंधन।
3. जल स्रोतों जैसे हैंडपंप, कुओं, तालाबों आदि के पास जलभराव से बचना
4. किचन गार्डन, एनएडीईपी और कम्पोस्ट पिट आदि के माध्यम से ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन।
5. पानी और व्यक्तिगत स्वच्छता के सुरक्षित भंडारण और संचालन को बढ़ावा देना।
6. समुदाय द्वारा शौचालयों के निर्माण और उपयोग के लिए जागरूकता पैदा करना।
7. स्वच्छता और उसके प्रभाव के बारे में जागरूकता अभियान

जाँच - परिणाम

बाल श्रम रायपुर में गली के बच्चों की उपस्थिति काफी अधिक है; शहर के फुटपाथों पर अपने माता-पिता के साथ जीवित रहने वाले बीमार बच्चों को सड़कों पर घूमते हुए देखना एक सामान्य परिदृश्य है। रायपुर में बाल श्रम अधिक है।

गरीब परिवारों से घरेलू नौकरों के रूप में, ये देखे जा सकते हैं बिचैलिए इन्हें लाते हैं। लड़के और लड़कियां बाल श्रम से ग्रस्त हैं, वे होटल, रेस्तरां, मैकेनिक की दुकानों, वेल्डिंग कार्यों, समाचार पत्र बेचने, हार्डवेयर की दुकानों, बीड़ी बनाने, कूड़ा बीनने और अन्य में लगे हुए हैं। अधिकांश बच्चे ऑटो रिक्शा में सहायक के रूप में देखे जाते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) ने स्कूलों की स्थापना की है और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से स्कूल चला रहे हैं। शिक्षा के बुनियादी ढांचे का साक्षरता स्तर मलिन बस्तियों में काफी पर्याप्त है क्योंकि उनके पास आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय या उनका एक संयोजन है। 2001 की जनगणना के अनुसार रायपुर शहरी समूह में स्लम आबादी की साक्षरता दर लगभग 71 प्रतिशत थी और स्लम में महिला साक्षरता लगभग 63 प्रतिशत थी। साक्षरता दर में वृद्धि के बावजूद, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या अधिक है। इनमें से अधिकांश ड्रॉपआउट श्रम बाजार में खींचे जा रहे हैं। यह चिंता का विषय है।रायपुर शहरी समूह में झुग्गी आबादी की स्थिति विषम है - हिंदू, मुस्लिम और ईसाई विभिन्न पड़ोसी राज्यों जैसे उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश से और आसपास के गांवों और जिलों से व्यापार, उद्योग और में बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में चले गए हैं। अन्य अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियाँ दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों के रूप में कार्यरत हैं और बाजार में मजदूरों के रूप में काम करती हैं। मलिन बस्तियों में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा हिंदी और उड़िया है। मौजूदा सूचना के अनुसार 65: मलिन बस्तियों को नियमित कर दिया गया है, हालांकि, नियमित बस्तियों में कुछ घरों के पास कार्यकाल की सुरक्षा है। रायपुर शहरी समूह में मलिन बस्तियाँ, राज्य में कहीं और, राज्य और केंद्र सरकार, नगरपालिका, निजी और अन्य लावारिस भूमि पर स्थित हैं, मलिन बस्तियों को स्थान और भूमि उपयोग के आधार पर आपत्तिजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है जैसे - नदी के किनारे पर

Scanned by CamScanner

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-9* October (Part-1) 2021
Innovation The Research Concept

स्थान निचले इलाकों, नालियों, सड़क हाशिये आदि। आरएमसी क्षेत्र में कुछ बहुत ही आपत्तिजनक मलिन बस्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया और समुदायों पर्यावरण की स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति मलिन बस्तियों में पर्यावरणीय बुनियादी ढांचा बहुत खराब है और अधिकांश मलिन बस्तियों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं जैसे उचित सड़कों, जल निकासी, संरक्षित जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट और शौचालय की सुविधा का अभाव है। विभिन्न योजनाओं के तहत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति खराब है, क्योंकि निर्धारित कर्मचारियों द्वारा रखरखाव की कमी है और परिणामस्वरूप उनका उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरी मुख्य समस्या ढकी हुई नालियों और सीवर की सुविधा का अभाव है। चूंकि अधिकांश मलिन बस्तियां सीमांत क्षेत्रों में स्थित हैं, जो नालियों पर अतिक्रमण कर रही हैं, उनमें से अधिकांश में भौतिक वातावरण खराब गुणवत्ता का है। इसके अलावा इन बस्तियों में सामुदायिक सुविधाओं और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच सीमित है और पर्याप्त नहीं है। सभी मलिन बस्तियों में, स्वास्थ्य केंद्र पर्याप्त रूप से दवाओं से सुसज्जित नहीं हैं और परिवारों को खुले बाजार से दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान करने के लिए भी सुसज्जित नहीं हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि मलिन बस्तियों में प्रचलित सबसे आम बीमारियों में गैस्ट्रो-एंटराइटिस, मलेरिया, डायरिया, हैजा, टाइफाइड, कुपोषण, दाद आदि शामिल हैं। इन स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए निगम 3 प्रसूति अस्पताल, 1 सरकारी अस्पताल और कई स्वास्थ्य केंद्र चलाता है। आरएमसी ने प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना भी शुरू की है और इसे गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। उनकी भागीदारी से, महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ियों और पहाड़ी क्षेत्रों में, कई शहरी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए। यहां सरकारी औषधालय भी हैं, जिनमें गरीबों का आना-जाना लगा रहता है। शहरी क्षेत्रों और गांवों के गरीबों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए रायपुर आना पड़ता है अतः स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। बुनियादी ढांचा झुग्गी-झोपड़ी की आबादी की बुनियादी सेवाओं तक पहुंच झुग्गी-झोपड़ी के लोगों और सामान्य तौर पर शहर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता का एक प्रमुख संकेतक है। मलिन बस्तियों में बुनियादी ढांचे तक पहुंच में सुधार की काफी गुंजाइश है। अपवाद के साथ, अन्य सभी झुग्गी बस्तियों में पर्याप्त पेयजल सुविधा, व्यक्तिगत शौचालय और सार्वजनिक शौचालय, जल निकासी और कचरा निपटान तक पहुंच का अभाव है। उदाहरण के लिए, अध्ययन से पता चलता है कि घरों के एक बहुत छोटे हिस्से के पास सीधे पानी की आपूर्ति का कनेक्शन है और कुछ हैंडपंपों के अलावा 2-3 नलों पर निर्भर हैं, जिनमें से अधिकांश काम नहीं कर रहे हैं। अपवाद मलिन बस्तियां हैं जहां अधिकांश घरों में सीधे पानी का कनेक्शन है। लेकिन कई मलिन बस्तियों में पीने का पानी पीने योग्य नहीं है। दूसरी समस्या पानी की आपूर्ति की अवधि (30-45 मिनट) और आपूर्ति की आवृत्ति (48 से 72 घंटे) से संबंधित है। शौचालय की सुविधा के मामले में, जबकि कई घरों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है, बड़े घरों के आकार के कारण, खुले में शौच एक आम बात है। विभिन्न योजनाओं के तहत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति खराब होने के कारण रखरखाव का अभाव है और परिणामस्वरूप उनका उपयोग नहीं किया जाता है। सड़क के बुनियादी ढांचे के संदर्भ में, अधिकांश मलिन बस्तियों में सड़कें हैं, लेकिन अधिकांश उप-गलियां पक्की नहीं हैं और स्ट्रीट लाइटिंग अपर्याप्त है। स्ट्रीट लाइटिंग ज्यादातर मुख्य पहुंच वाले रास्तों पर होती है और भीतरी सड़कों पर अंधेरा रहता है, जिसे आबादी की अधिकांश महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए चिंता के रूप में व्यक्त किया। हालांकि, एक मुख्य समस्या, जो सभी मलिन बस्तियों में मौजूद है, सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी की कमी और सामाजिक सुरक्षा की सीमित पहुंच है। उदाहरण के लिए, सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों और मिट्टी के तेल के वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली अक्सर अपर्याप्त होती है और आवश्यक वस्तुओं का डायवर्जन होता है। इन सुरक्षा जालों तक पहुंच की कमी और सरकारी योजनाओं के बारे में सीमित जानकारी उनकी भेद्यता को बढ़ाती है और उन्हें गरीबी के जाल में धकेल देती है। बिजली के संबंध में, ये मलिन बस्तियां वैध कनेक्शन से वंचित हैं; बल्कि वे अवैध रूप से बिजली को जोड़ रहे हैं और इस सुविधा को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। शराब का सेवन झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों में शराब के सेवन की आदत इसकी पहचान के रूप में मुख्य समस्या है। हालांकि लोग हाथ से मुंह स्थिति में रह रहे हैं, इस उद्देश्य के लिए एक बजट अलग रखा गया है। इससे समाज का सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। पैसे बचाने की कोई आदत नहीं है बल्कि वे पैसा खर्च करते हैं। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के पास अधिक आय नहीं है जो बाल श्रम का एक अन्य कारण है। वास्तव में लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाओं, सुरक्षित पेयजल, बाल स्वास्थ्य देखभाल, आय सृजन गतिविधियों, सरकारी योजनाओं आदि के संदर्भ में विकास के संबंध में जागरूकता की कमी है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार आएगी और उनके लिए सब कुछ करेगी। लोगों के साथ बातचीत के दौरान यह भी पुष्टि हुई कि आज तक किसी भी एनजीओ ने इन झुग्गियों का दौरा नहीं किया है, इसलिए एनजीओ की ओर से कोई पहल नहीं की गई थी। इसलिए, वर्ल्ड विजन इंडिया पहला एनजीओ होगा, जो इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेगा। समग्र रूप से लोगों/समुदाय के विकास के लिए। आरंभ करने के लिए, संगठन को इन मलिन बस्तियों की समस्या और जरूरतों से परिचित होना होगा, जिन्हें यहां नीचे रखा गया है-

Scanned by CamScanner

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-9* October (Part-1) 2021
Innovation The Research Concept

समस्या की आवश्यकता

गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं का अभाव-बिजली स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, हैंडपंप, सड़क/गली, जल निकासी, आश्रय बिजली का कानूनी कनेक्शन, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच, काम करने वाले हैंडपंप, सड़क/सड़कों और नालों का निर्माण, उचित आश्रय।

2. रोजगार की कमी - मसाला पीसना, पापड़ बनाना, अचार बनाना और पैकिंग करना, झाड़ू बनाना, मोमबत्ती बनाना, सिलाई, चटाई बनाना, दुकान खोलना, वस्तुओं की बिक्री और खरीद जैसे गृह रोजगार - एसटीडी, पीसीओ, टेंट हाउस, स्टील फर्नीचर के ढाबे खोलना और संचालन करना, टीवी रेडियो रिपेयरिंग, मोटर रिवाइंडिंग, ऑटो गैरेज, सैलून, साइकिल रिपेयरिंग, टेलरिंग, दुकानें खोलना, पान-गुमती, वेंडिंग पोल्ट्री, ड्राइविंग।

3. शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी। विभिन्न विषयों पर जागरूकता शिविर का आयोजन मोटिवेशन कोर्स कराया जाएगा। - स्कूल और टीकाकरण बच्चों के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र होना चाहिए।

4. मलिन बस्तियों में आंगनवाडी (प्री स्कूल) का अभाव आंगनबाडी (पूर्व विद्यालय) मलिन बस्तियों में होना चाहिए -

5. सुरक्षित पेयजल सुविधाओं का अभाव। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

6. उचित आवास का अभाव, अस्वच्छ, अधिक भीड़भाड़ वाला क्षेत्र या स्थान की तलाश की जा सकती है। यहाँ घरों की मरम्मत की जरूरत है । वेंटिलेशन की आवश्यकता है।

अत्यधिक शराब का सेवन को रोकने हेतु विशेष जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और शराब की खपत के नकारात्मक पक्षों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। महिलाओं को शराब पीने के नुकसान के बारे में जागरूक किया जा सकता है और शराब के खिलाफ एक मजबूत कदम उठाने के लिए एकता में लाया जा सकता है। - युवाओं को अलग से ट्रेनिंग इनपुट दिया जा सकता है ताकि उन्हें शराब और अन्य नशीले पदार्थों के हानिकारक प्रभाव का एहसास हो सके।

सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी

पूरे समुदाय के लिए जागरूकता सह प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सूचना केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। यदि यह उपलब्ध हो तो लोगों को नियमित रूप से केंद्र का दौरा करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

केंद्र को हर दिन/सप्ताह/माह अद्यतन किया जा सकता है। युवाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

युवाओं को चाहिए कि वे सूचना केंद्रों के रखरखाव का हिस्सा बनें।

एकता/सामुदायिक भावना और सामाजिक जीवन का अभाव जैसे विषयो पर लोगों को जागरूकता कार्यक्रम दिया जाना चाहिए। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और इसके लिए कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की ओर से निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए।

इस संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से होने चाहिए। - युवाओं को एसएचजी और सामान्य आईजीपी के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि उनके बीच एक साथी भावना, सामुदायिक भावना पैदा की जा सके।

उनके मूल अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में ज्ञान का अभाव। फिर से समुदाय को इस विषय के संबंध में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम देना होगा।

ज्ञान होने के बाद उन्हें इसके लिए लड़ने की रणनीति तैयार करनी चाहिए। जागरूकता कार्यक्रमों में महिलाओं को बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है -

1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लोगों को वह मिलना चाहिए जो उनके कारण है न्याय के साथ जागरूकता का निर्माण जरूरी है।

2. स्लम क्षेत्र में भूमि कानूनी दस्तावेजों की कमी लोगों को उनके भूमि दस्तावेज प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए

निष्कर्ष

स्पष्ट रूप से, छत्तीसगढ़ में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए विकास एजेंसियों सरकार और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा कुछ पथ-प्रदर्शक पहल की गई हैं। हालांकि, सामुदायिक विकास की कुछ कठोर और पुरानी प्रथाएं भी हैं, जो न केवल अपनी बढ़त और उद्देश्य खो चुकी हैं, बल्कि दृष्टिकोण और बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के मामले में भी दायित्वहीन बन गई हैं। इसलिए, यह अध्ययन, विकास एजेंसियों को रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य और भारत में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के समग्र विकास के लिए उनकी आजीविका, स्वास्थ्य और विशेष रूप से उनकी आजीविका, स्वास्थ्य और विशेष रूप से उनके समग्र विकास के लिए रणनीतियों की उचित सिफारिशें करने के लिए आमंत्रित करता है।

Scanned by CamScanner

सन्दर्भ ग्रन्थ सुची

1. हब कार्ल एंड शर्मा, ओ.पी., भारत की जनसंख्या वास्तविकतारू जनसंख्या बुलेटिन में परिवर्तन और परंपरा का समाधान; जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो का प्रकाशन, खंड 61, संख्या 3, सितंबर 2006।
2. चंद्रमौली, डॉ. सी. (2003)। चेन्नई में झुग्गियांरू एक प्रोफाइल। पर्यावरण और स्वास्थ्य पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही, चेन्नई, भारत, दिसंबर 15-17।, चेन्नई, मद्रास विश्वविद्यालय और पर्यावरण अध्ययन संकाय, यॉर्क विश्वविद्यालय। 30 जून 2009 को पुनःप्राप्त,
3. श्रद्धा, ए., और भारती, बी.एम. (200)। शहरी मलिन बस्तियों में प्रजनन स्वास्थ्य। द जर्नल ऑफ़ ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी इन इंडिया 56(3), 255-257।
4. रुस्तगी, पी., सरकार, एस., और जोद्दार, पी. (2009)। भारतरू शहरी गरीबी रिपोर्ट 2009। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 30 जून 2009 को पुनःप्राप्त,
5. लक्ष्मणन, वी. (2007)। चेन्नई की मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य और शिक्षा में एक सांख्यिकीय अंतर्दृष्टि। 30 जून 2009 को पुनःप्राप्त,
6. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), प्रजनन और बाल स्वास्थ्यरू जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण 2002-04। मुंबईरू भारत सरकार, 2006।

Scanned by CamScanner